तीय मूल के लोग और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या करीब दो करोड़ होगी । अगर ऐसा कहा जाए कि दो प्रतिशत भारतीय दुनिया के कोने-कोनेमें बस गये हैं तो गलत नहीं होगा ।

विदेशों में गये भारतीयों से भारत सरकार को बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । मेरे अनुमान से विदेशों में जाने वाले भारतीयों को दो श्रेणियों हैं- अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन बैल्जियम, पुर्तगाल, स्वीडन आदि देशों में जाने वाले भारतीय उन्हीं देशों में बसने का सपना रखते हैं । साथ-साथ इन देशों में जाने वाले भारतीय उच्च शिक्षा प्राप्त भी होते हैं लेकिन अमरीका, अरम देश और दक्षिण पूर्व एशिया में जाने वाले भारतीयों में मजदूर वर्ग की तादाद ज्यादा होते है । इसी वर्ग का शोषण ज्यादा होता है । भारतीय मैनपावर एक्सपोर्ट एजेन्सियों सब से पहले ऐसे मजदूरों का नहीं उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारो का भी शोषण करती है । विदेश में जाने वाले मजदूरों को कोई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कई बार जान भी देनी पड़ती है । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए और बढ़ती हुई घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए मैं सरकार से इस सिलसिले में कुछ कदम उठाने की मांग करता हूं ।

सबसे पहले देश के विभिन्न शहरों में जो मैनपावर एक्सपोर्ट एजेसिंयों हैं उनको अपने कार्य की पूरी जानकारी भारत सरकार को या संबधित राज्य सरकार को देना अनिवार्य किया जाये । इसी के साथ-साथ भारत सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे कि जिससे कोई भी भारतीय धोखे से विदेश में न जांए । विदेश मंत्रालय और विदेशों में स्थिति भारतीय दूतावास इस मामले पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं । विविध देशों में सरकारों से समन्वय करके वहां के रिक्त स्थानों को भारत में प्रकाशित होने वाली "रोजगार समाचार" जैसे वीकली में प्रकाशित कर सकते हैं जिससे बेरोजगार या विदेशों में जाने के इच्छुक लोग बिचौलियों के धोखाधडी से बच सकेंगे । उसी तरह भारतीय दूतावास अपने पास एक कम्प्यूटराइज्ड डाटा रख सकता है और संबधित विदेशी सरकारों को भी उपलब्ध करा सकता है । बहुत से देश चाहते हैं कि विदेशी उनके देश में नौकरियों के लिए आयें लेकिन वे वहां बसें नहीं । अगर भारत सरकार, वभिन्नि राज्य सरकारें और भारत सरकार के उपक्रमों में कार्यरत और विदेशों में जाने के इच्छुक कर्मचारियों को एक या दो वर्ष के लिए लियन पर जाने की व्यवस्था करे तो ऐसी व्यवस्था में भारतीयो को बहुत बरीयता दी जाएगी । उनके स्थान पर यहां के बेरोजगारी को नौकरियों उपलब्ध होगी परिणामतः भारत में विदेशी मुद्रा बडें पैमाने पर आ सकती है और आएगी ।अतः मैं आपसे अनुरोधा करूंगा कि इस मामले का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक संसदीय समिति बनायी जाए जिसमें सांसदों के अलावा देश में विभिन्न वर्गों से भी सुझाव लिए जांए और विदेशों में गए इस देश के दो प्रतिशत लोगों के कल्याण के लिए कोई ठोस कदम उठाएं जाएं । पिछले कुछ सालों से प्रति वर्ष करीब दस हजार शिकायतें आ रही है ।उनको दूर करने की पूरी कोशिश की जाए । मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार इन बातों को गंभीरता को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही कदम उठाएगे । धन्यवाद ।

Violation of guidelines Divenmn and and Misappropriation of undsunderEmployment Assurance Schemes Sponsored by Central Govt in a Number of Stages

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार) : महोदया, मैं सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन में जो कमजोरियां हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । यह सुनिश्चित रोजगार योजना हम सभी को मालूम है ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने के निर्मित हैं और इस योजना का उद्देश्य हैं कि गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में जो परिवार है उनमें एक परिवार से दो व्यक्तियों को एक साल में एक सौ दिन काम देना सुनिश्चित किया जाए । महोदया, यह अंसगठित मजदूरों का एक मामला हैं । हम लोगों ने इसके पहले आज के हाउस में सगंठित मजदूरों की समस्याओं

पर काफी बहस की, काफी समय उस पर दिया । जो संगठित हैं, उनके सामने इतनी परेशानियां हैं । जो असंगठित है उनको परेशानियों को अभी हम अनुमान भी नहीं लगा पा रहें हैं । मैडम, इस कार्यान्व्यन की कमजोरियों के बारे में हाल में जो हम लोगो के पास नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आई हैं, वह जो दासतां कह रही है वह अजीबो-गरीब हैं । उसमें और हम लोग गांवों के अंदर जो सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन के मामले को देख रहे हैं । तो दोनों मे मेल पाते हैं । लेकिन यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो मेरे पास है (नम्बर 3,1997) इसमें इस योजना के कार्योन्यवयन के इवैल्यूएशन एण्ड आडिट का काम किया गया है । 22 राज्यों के 98 डी.आर डी. एल.का आडिट किया गया है। उससे भी बिल्कुल स्पष्ट है कि उस योजना के कार्यान्वयन क निर्मित जो गाइडलाइंस है उनका वायोलेशन बडे पैमाने पर हो रहा है । दूसरा योजनाओं के लिए दूसरी गतिविधियों के लिए फंड का डाइवर्जन हो रहा है, फंड का मिसएप्रोप्रिएशन हो रहा है गाइडलाइंस के वायोलेशन के चलते फंड का मिसएप्रोप्रिएशन और डाइवर्जन हो रहा है । मैनें कहा मैंडम कि अजीबो-गरीब दासतां हैं । मैं इसका एक उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं उदाहरण स्वरूप इस रिपोर्ट से ही । इसका पैरा 3.7.1 हैं । इस रिर्पोट का चैप्टर 3 है इसमें पैरा 3.7.1 है ।

"…In Nagaland, Rs. 39.05 lakhs were reportedly paid to the group leaders and MLAs and a State Government officials' officebearer of a political party..."

9-00 म.प.

पोलिटीकल पार्टी के ऑफिस बेयरर्ज को राशि इस सुनिश्चित रोजगार योजना की राशि में से …(**व्यवधान**)… नहीं है तो ग्रुप लीडर्ज कौन है, मैडम यह दिमाग दिया है,डाइवर्शन आफॅ फंड का जो मामला है, आप दो मिनट का समय कुछ बढ़ायेंगी तो मुझे यह आशा है…(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापडे) : नहीं, ओझा जी, आप स्पेशल मेंशन कर रहे हैं । आप इतना लंबा बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा जरा संक्षेप में बोलिएगा ।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : लंबा नहीं हैं । एक रोज हम लोगों ले बंगाल के फंडर्ज के डाइवर्जश पर बात की थी । मैं इस रिपोर्ट को केवल पढ़ कर सुना देना देता हूं जो हम समझते हैं । कि 12-13राज्यों के मामले में हैं । 1993 से लेकर 1996 के बीच के हैं । आंध्र प्रदेश 712 लाख …(**व्यवधान**)..

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापडें) : आप रिपोर्ट को क्यों प़ढ़ रहे हैं ? आपको जा उसके बारे में कहना है, वह कहिए और संक्षेप में कहिए । रिपोर्ट पढेंगे तो बहुत वक्त लग जायेगा ।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : आंध्र प्रदेश, असम,बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड काश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, और अन्य राज्यों के मामले में कहा गया है कि 53 करोड़ रूपये का ड्राइवर्शन हुआ । मैडम, एक रिपोर्ट है कि 180 दिन तक पर्सनल एकांउट में वह रूपया रखा गया । रिपोर्ट में, 180 दिन के लिए नागालैंड में है और 56लाख रूपये जो सूद हुआ उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था । इस तरह से मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग, कई बार हाउस के अंदर सुनिश्चित रोजगार योजना और अन्य ग्रामीण योजनाओं के कार्यान्वयन में जो कमजोरियां हैं, फंड का जो डाइवर्शन हैं, मिस एप्रोप्रिएशन है, उसको हम चर्चा करते रहे हैं और नियंत्रक और महालेखाकार की रिपोर्ट से अब यह बिल्कुल प्रमाणित हो चुका हे मैडम, मैं इसके जरिए मांग करना चाहता हूं कि यह जो मिसएप्रोप्रिएशन है, फंडर्ज का डावर्शन हैं और गाइडलाइंस का जो उल्लघंन हो रहा है इसकी जवाबदेही किसी पर बनती है या नहीं ? इसकी जवाबदेही बनती है । जो मिनिस्ट्री आफ् रूरल एरियाज एंड एम्प्लायमेंट है इस पर फानइसिंग

प्लानिंग गाइड लाइंस और इसके इवेलूएशन की जवाबदेही है। राज्य के अंदर सैक्रेटरी के सभापतित्व में स्टेट लेवल कोआर्डिनेशन कमेटी मॉनिटरिंग करती है, और जिला के अंदर इसके इंप्लीमेंटैशन की जवाबदेही है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : ओझा साहब स्पेशल मेंशन के लिए हर माननीय सदस्य को तीन मिनट का वक्त दिया जाता है। आपका वक्त बहुत ज्यादा होता जा रहा है। आप संक्षेप में बोलेगे तो औरों का नंबर भी बोलने का जल्दी आएगा। आप समय का ध्यान रखिएगा। मैं नही चाहूंगी कि बार-बार मैं किसी सदस्य को रिमांइड कराऊं कि आपका वक्त खत्म हो रहा है, आप जरा संक्षेप में बोलिए, यह कहने के लिए हमें भी अच्छा नहीं लगता।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : महोदया, मैं यह मांग करता हूं कि जो हमारे समाज का सब से गरीब तबका है जो अन-आर्गेनाइज्ड है और जिसके लिए हम बराबर चिंता व्यक्त करते हैं और अभी हाल ही में प्रधान मंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार देशद्रोह है और ऐसी योजना के अंदर आफिशियल के जरिए उच्च पदस्थ लोगों के स्तर पर इस तरह से डाइवर्शन हो रहा है, यह बहुत ही गंभीरी मामला है। इसको रोकने के लिए कारगर कदम अविलम्ब उठांए जांए, क्योंकि एक मामला तो प्रकाश में आ गया है, कि 56 लाख रूपया सूद एक व्यक्ति ने इसके लिए ले लिया और 180 दिन तक अपने एकाउंट में उसने पैसा रखा। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके खिलाफ कार्यवाही भी नहीं हुई। महोदया, इसके लिए जो दोषी पाए जांए उनके ऊपर कार्यवाही हो और इस बारे में तथा इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में एक स्टेटमेंट संबधित मंत्री के द्वारा जो यह नियंत्रक और महालेखाकार की रिपोर्ट हैं उसके प्रसंग को ले करके हाउस के सामने रखी जाए। धन्यवाद।

Alleged holding of Disputed Shares Securities Oitiflcates "fo the extaut of Rs. 2970 crores by Canara Banlc^ Can Bank Mutual Fund and Can -Bank . Financial. Services

SHRI R. K. KUMAR (TamJl Nadu): Madam, I rise to draw the attention of the Government through {his House to a very disturbing report relating .to the Canara Bank. The Canara Bank is one of the fine institutions among the na-tionaiised banks with 90 years' standing and I had the privilege of serving on its Board for one term.

Madam, according to a report in *The* Indian Express of 4.7.1997, the Canara Bank seems fo be holding Rs. 2,162 crores worth of shares and securities, of which the title is disputed. The Bank doesii't have title to these ' shares: and 'securities.

For another Rs. 600 cibres. of shares and securities of Canbank Mutual Fund under the scheme called Can Star, the liability is likely tl^ fall on the Ca'nara fiarik. Madam, the origin- of this is in the pursuit of Seeking higher profits Canbank Financial Services took deposits from various public sector undetiakings. There was a ceiling on interest of 10 per cent at that time, but this sub'si-diary of Canara Bank took deprisits fiom various PSUs' to beat the deposit-interest ceiling restriction under the Portfolio Management Scheme, i.e., you give the money, I am going to invest in shares and securities and I will get you a minimum return of 20 per cent. This is how the money was taken. This money was" advanced to various brokers in Mumbai. TheSe brokers with this money took *the* share price up, up and up and ultimately the sCafti broke oiit in (1991--92.) and what had happened? These public sector undertakings -are • now saying, "We don't want your shares or securitie's. Give,us back bur money with interest." So, the Canara Bank is saddled with Rs. 2,162 croers